

निर्मलजीत कौर जे.(जज)के सम्मुख

खुस्टिल-याचिकाकर्ता

बनाम

विरेन्द्र उर्फ बिरेन्द्र उत्तरदाता

सीआर No.5306

04 अक्टूबर, 2019

ए. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-ओ. 9 आर. एल. 13, ओ. 5 आर. एल. 19-भारत का संविधान, 1950 अनुच्छेद - सीमा अधिनियम, 1963-निचली अदालत के साथ-साथ अपीलीय अदालत द्वारा आदेश 9 नियम 13 सी. पी. सी. के तहत आवेदन को खारिज करने के आदेश के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका-एकतरफा फैसले और डिक्री को दरकिनार करने के खिलाफ

बी. आदेश 5 नियम 19 सी. पी. सी.-अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया-सेवारत अधिकारी का कोई भी हलफनामा आवेदक की सेवा के लिए रिकॉर्ड पर नहीं आया-प्रोसेस सर्वर की रिपोर्ट विरोधाभासी-रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कोई भी गवाह उपलब्ध नहीं है, जबकि एक गवाह ने विधिवत हस्ताक्षर किए हैं-ऐसे गवाह जिनकी ट्रायल कोर्ट के समक्ष जांच नहीं की गई है-रिपोर्ट स्वयं संदेह से घिरी हुई है।

ग. सीमा अधिनियम-सीमा की अवधि एकतरफा कार्यवाही की जानकारी की तारीख से शुरू होगी, न कि मुकदमे के निर्णय और डिक्री के पारित होने की तारीख से-इस प्रकार, एकतरफा निर्णय और डिक्री को अलग रखा जाता है-आवेदक/प्रतिवादी को लिखित बयान दायर करने और साक्ष्य देने और छह महीने की अवधि के भीतर मुकदमा समाप्त करने के लिए समय दिया जाता है।

अभिनिर्धारित किया कि, निर्णय लेने के लिए, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, प्रक्रिया प्रोसेस सर्वर द्वारा प्रस्तुत अस्वीकृति की रिपोर्ट को देखना उचित होगा। उसी का एक अवलोकन, जो स्थानीय भाषा में है, दर्शाता है कि यह विरोधाभासी है। यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि कोई गवाह उपलब्ध नहीं है, जबकि एक गवाह, प्रदीप ने विधिवत हस्ताक्षर किए हैं। वास्तव में, इस गवाह के पते का भी उल्लेख किया गया है। इसके बावजूद, ऐसे किसी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है। दोनों में से कोई भी पक्ष उक्त प्रदीप के अस्तित्व या अस्तित्व को स्थापित नहीं कर सका। इसलिए रिपोर्ट अपने आप में संदेह से घिरी हुई है। याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील के इस तर्क पर विवाद करते हुए कि प्रोसेस सर्वर ने आदेश 5 नियम 19 सी. पी. सी. के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया और नियम 17 के तहत वापस किए गए समन को सेवारत अधिकारी के हलफनामे द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, प्रतिवादी-वादी के विद्वान वकील ने प्रोसेस सर्वर द्वारा समन पर शपथ पत्र को समर्थन किया है।

(निर्मलजीत कौर, जे.)

हालाँकि, उक्त समर्थन शपथ पत्र के सत्यापन के लिए सी. पी. सी. में निर्धारित आवश्यक अवयवों को पूरा नहीं करता है। यहाँ तक कि प्रोसेस सर्वर का नाम भी स्पष्ट नहीं है। शपथ पत्र पर भी ऐसा नहीं है। भले ही उक्त विसंगति को नजरअंदाज कर दिया जाए, लेकिन तथ्य यह है कि कथित स्वतंत्र गवाह प्रदीप की पहचान स्थापित करने में विफलता, प्रोसेस सर्वर द्वारा रिपोर्ट में विशिष्ट कथन के साथ कि कोई स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं था, विरोधाभासी होने के कारण, समन की सेवा पर संदेह की छाया डाल दी है।

(पैरा 7)

आगे अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी/वादी के लिए विद्वान वकील का अगला तर्क कि आदेश 9 नियम 13 सी. पी. सी. के तहत आवेदन निराशाजनक रूप से समय से वर्जित था, इसलिए, कोई मदद नहीं होगी, एक बार जब अदालत यह निष्कर्ष निकालती है कि याचिकाकर्ता को मुकदमे के लंबित होने के बारे में पता नहीं था क्योंकि यह विवादित नहीं है कि देरी जानकारी की तारीख से शुरू होती है। वर्तमान मामले में, जानकारी की तारीख वह तारीख है जब उसकी माँ को फांसी की याचिका में समन प्राप्त हुआ था और उसने फांसी की याचिका में समन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। यह तर्क कि आदेश 9 नियम 13 के तहत आवेदन में जानकारी की किसी भी तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है, ताकि अदालत को जानकारी की उस तारीख के बारे में पता चल सके जिससे सीमा को गिना जा सके, यह भी मदद नहीं करता है क्योंकि याचिकाकर्ता ने आदेश 9 नियम 13 सी. पी. सी. के तहत आवेदन दायर किया था।

(पैरा 10)

कुणाल डावर, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

प्रतिवादी के वकील सर्वेश कुमार गुप्ता के साथ विकास बहल, Sr.Advocate।

निर्मलजीत कौर, जे।

- (1) वर्तमान पुनरीक्षण याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (Sr.Division), फरीदाबाद द्वारा पारित 30.05.2017 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता, जो मुकदमे में प्रतिवादी संख्या 3 थे, द्वारा दायर आदेश 9 नियम 13 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन को खारिज कर दिया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता के 748 के खिलाफ याचिकाकर्ता की अपील को खारिज करते हुए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, फरीदाबाद द्वारा पारित 03.09.2014 के एकतरफा फैसले और डिक्री के साथ-साथ 19.08.2019 के फैसले और आदेश को रद्द करने की मांग की गई है।

आदेश 9 नियम 13 सी. पी. सी. के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन की अनुमति देने के लिए एक और अनुरोध के साथ 30.05.2017 का आदेश जारी किया गया।

(2) संक्षिप्त तथ्य, जिसके कारण वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दायर करना आवश्यक हो गया है, तब शुरू होता है जब प्रतिवादी-वादी ने उक्त मुकदमे में प्रतिवादियों के खिलाफ बेचने के लिए समझौते के एक विशिष्ट प्रदर्शन के माध्यम से कब्जे के लिए एक मुकदमा दायर किया जिसमें आरोप लगाया गया कि श्री अशोक कुमार शर्मा और सुमित चानना, प्रतिवादी Nos.1 और उक्त मुकदमे में 2 ने प्रतिवादी-वादी के साथ दिनांक 10.07.2008 को बेचने के लिए एक समझौता किया था। 60.00 लाख और जिसमें से, प्रतिवादी-वादी ने रुपये की बकाया राशि का भुगतान किया था। 20.00 लाख। इसके बाद, उपर्युक्त मालिकों ने संपत्ति को वर्तमान याचिकाकर्ता-खुशदिल को बेच दिया, जो मुकदमे में प्रतिवादी नंबर 3 थे, बिक्री-विलेख दिनांक 19.03.2010 के माध्यम से। वर्तमान याचिकाकर्ता और प्रतिवादी Nos.1 और 2 को एक तरफा आगे बढ़ाया गया था और मुकदमे का फैसला निर्णय और 03.09.2014 दिनांकित एक एकतरफा डिक्री के माध्यम से इस आधार पर किया गया था कि याचिकाकर्ता-प्रतिवादी संख्या 3 को जारी किया गया नोटिस इनकार की रिपोर्ट के साथ वापस प्राप्त किया गया था। उपरोक्त डिक्री के पारित होने के बाद, प्रतिवादी-वादी ने 17.01.2015 पर निष्पादन आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन का एक नोटिस 01.04.2015 के लिए 04.03.2015 पर जारी किया गया था और एक बार फिर 23.04.2015 के लिए भी जारी किया गया था। यह आरोप लगाया जाता है कि उक्त समन वर्तमान याचिकाकर्ता की मांग को प्राप्त हुए थे, चूंकि उन्होंने एक बार फिर इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, इसलिए इनकार की रिपोर्ट दी गई थी। हालांकि, याचिकाकर्ता-निर्णय-ऋणदाता 23.04.2015 पर निष्पादन कार्यवाही में उपस्थित हुए। इसके बाद, याचिकाकर्ता-निर्णय देनदार ने 11.05.2015 पर 03.09.2014 दिनांकित एकतरफा निर्णय और डिक्री को दरकिनार करने के लिए आदेश 9 नियम 13 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन दायर किया। हालांकि, उक्त आवेदन को 30.05.2017 दिनांकित आदेश और निर्णय के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता-प्रतिवादी संख्या 3 ने तदानुसार दिनांकित 30.05.2017 आदेश के खिलाफ अपील दायर की, जिसे भी 19.08.2019 पर खारिज कर दिया गया था। इसलिए, वर्तमान संशोधन 30.05.2017 के आदेश और निर्णय के साथ-साथ 19.08.2019 के आदेश के खिलाफ दायर किया गया है।

(3) विवादित आदेशों को रद्द करने के लिए प्रार्थना करते हुए, याचिकाकर्ता-प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उक्त आदेश 5 नियम 19 सी. पी. सी. के अनिवार्य प्रावधानों के पूर्ण गैर-अनुपालन में पारित किए गए हैं। कथित सेवा सत्यापन के लिए सेवारत अधिकारी का कोई हलफनामा रिकॉर्ड पर सामने नहीं आया है और न ही याचिकाकर्ता की सेवा की कोई रिपोर्ट है। प्रोसेस सर्वर सी. पी. सी. के आदेश 5 नियम 17 और 19 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा। रिपोर्ट विरोधाभासी है।

(निर्मलजीत कौर, जे.)

एक ओर यह कहा गया है कि वहाँ कोई स्वतंत्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं है और दूसरी ओर एक प्रदीप ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसे पेश नहीं किया गया था। उचित पते पर पंजीकृत डाक द्वारा कोई समन नहीं भेजा गया था जिसमें स्वीकृति देय थी। अदालत ने गलत तरीके से दर्ज किया है कि देरी हुई थी। देरी जानकारी की तारीख से शुरू होती है और याचिकाकर्ता को तब पता चला जब उसकी माँ को समन प्राप्त हुआ और फांसी की याचिका की एक परत उसकी माँ के पास छोड़ दी गई। यह आगे तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता का मामला गुण-दोष के आधार पर अच्छा है और इसलिए, उसकी निंदा नहीं की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार, संपत्ति उनके पिता द्वारा खरीदी गई थी, जो भारतीय वायु सेना में एक पूर्व सैनिक हैं, और जिन्होंने अपनी जीवन भर की बचत को उक्त संपत्ति खरीदने में निवेश किया है ताकि वे अपनी सेवानिवृत्ति के बाद आराम से रह सकें। घर के मालिक अशोक कुमार शर्मा और उनके बेटे सुमित चानना ने अपनी मां शकुंतला के पक्ष में पूर्ण और अंतिम समझौता किया है और सभी दस्तावेज जैसे कि स्वामित्व प्रमाणन, वसीयत आदि को उनकी मां के पक्ष में निष्पादित किया गया है। उक्त लेन-देन को सुमित अरोड़ा और आर.के. चावला द्वारा सुगम बनाया गया था, जिन्होंने दस्तावेजों को भी देखा है। इसके बाद, याचिकाकर्ता की माँ ने याचिकाकर्ता के पक्ष में बिक्री विलेख को निष्पादित किया। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रतियों के साथ-साथ बिक्री विलेख को याचिकाकर्ता के इस संशोधन के रिकॉर्ड पर रखा गया है जिसमें रुपये की राशि के अलावा दो चेकों के माध्यम से 15.00 लाख। 22.00 लाख नकद में दिए गए थे, जो उनके पिता ने उनके खाते से निकाले थे। दूसरी ओर, प्रतिवादी-वादी के साथ बेचने का समझौता रुपये के विचार के लिए 10.07.2008 दिनांकित है। 60.00 लाख, जिसमें से 28.00 लाख रुपये का भुगतान बिक्री-विलेख के पंजीकरण के साथ किया जाना था।

(4) तदानुसार, प्रतिवादी-वादी, विरेन्द्र उर्फ बिरेन्द्र द्वारा पूरे घर को बेचने के समझौते के तहत बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया गया था, जिसकी अनुमति दिनांक 03.09.2014 के एक एकतरफा डिक्री द्वारा दी गई थी।

(5) प्रतिवादी-वादी के विद्वान वकील ने पुनरीक्षण याचिका का जोरदार विरोध करते हुए निम्नलिखित तर्क दिए:

(क) याचिकाकर्ता-प्रतिवादी संख्या 3 को जारी किए गए मुकदमे का नोटिस अस्वीकृति की रिपोर्ट के साथ वापस प्राप्त किया गया था और अदालत द्वारा प्रतीक्षा करने और मामले को कई बार बुलाए जाने के बाद ही उसे एकतरफा आगे बढ़ाया गया था।

(ख) यह तथ्य कि याचिकाकर्ता को इनकार करने की आदत है, इस तथ्य से स्पष्ट है कि में बाद का नोटिस भी

अस्वीकार की रिपोर्ट के साथ निष्पादन याचिका वापस प्राप्त की गई थी, लेकिन इसके बावजूद, याचिकाकर्ता उपस्थित हुआ। इसका मतलब यह है कि याचिकाकर्ता को विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमे के बारे में पता था, लेकिन उसने केवल कार्यवाही में देरी करने के लिए दूर रहने का फैसला किया क्योंकि वह संपत्ति उसके कब्जे में है, लेकिन निष्पादन कार्यवाही में उपस्थित हुआ, भले ही एक बार फिर रिपोर्ट इनकार करने की थी।

(ग) यह आगे तर्क दिया गया कि वादी को देरी और हतोत्साहित करने के लिए विशिष्ट प्रदर्शन के कई मुकदमों में यह सामान्य तरीका और रणनीति है।

(घ) याचिकाकर्ता द्वारा एडब्ल्यू(AW)2 टोनी के.जॉसफ के रूप में यह साबित करने के लिए पेश किया गया कि रामदास के बेटे प्रदीप के नाम से कोई भी व्यक्ति परिसर में नहीं रह रहा था और प्रोसेस सर्वर की रिपोर्ट में हमेशा सच्चाई और शुद्धता का अनुमान होता है।

(ङ) इसके अलावा, आदेश 9 नियम 13 सी. पी. सी. के तहत आवेदन लगभग पांच साल के अंतराल के बाद और देरी की माफी के लिए किसी भी आवेदन के बिना दायर किया गया था। मामलों में दिए गए फैसलों पर भरोसा रखा गया था। भारत संघ और अन्य बनाम राम प्रसाद पांडे और अन्य **2006 (6) एडीजे 635** और मूल चंद यादव उर्फ अशोक बनाम फूल सिंह और एक अन्य **2010 (5) आरसीआर (सिविल) 8** तर्क दें कि देरी को माफ करने के लिए आवेदन के अभाव में, मामले को गुण-दोष के आधार पर नहीं लिया जा सकता है।

(च) यह तथ्य कि याचिकाकर्ता जानबूझकर दावे में उपस्थित नहीं हुआ था, इस तथ्य से भी स्पष्ट था कि उसे निष्पादन आवेदन में दिनांक 05.12.2015 के आदेश के माध्यम से एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ाया गया था, लेकिन दिनांक 11.09.2019 के आदेश के अनुसार लागत के रूप में 1000 रुपये के भुगतान के अधीन बहाल किये गए थे।

(छ) मुकदमे की संपत्ति को बैंक के साथ गिरवी रखा गया था और इसके खिलाफ 65 लाख रुपये का भारी ऋण बकाया था। पूरी राशि का भुगतान प्रतिवादी-वादी द्वारा किया गया था। ऐसा करते समय, उन्होंने ऋण के लिए कुछ राशि का भुगतान करने के लिए याचिकाकर्ता से भी संपर्क किया था और इसलिए, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी-वादी द्वारा दायर मुकदमे के लंबित होने की जानकारी थी। वह उसी इमारत में रह रहा था, इसलिए वह लंबित मुकदमे के बारे में जानने के लिए बाध्य है जब ऋण की वसूली के लिए समानांतर कार्यवाही भी चल रही है।

(निर्मलजीत कौर, जे.)

(ज) वर्षों की संख्या बीत चुकी है। इस स्तर पर एकतरफा आदेश को दरकिनार करने से शिकायत और कठिनाई होगी।

(6) पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना गया।

(7) निर्णय लेने के लिए, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, **izksls loZj** द्वारा प्रस्तुत अस्वीकृति की रिपोर्ट को देखना उचित होगा। उसी का एक अवलोकन, जो स्थानीय भाषा में है, दर्शाता है कि यह विरोधाभासी है। यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि कोई गवाह उपलब्ध नहीं है, जबकि एक गवाह, प्रदीप ने विधिवत हस्ताक्षर किए हैं। वास्तव में, इस गवाह के पते का भी उल्लेख किया गया है। इसके बावजूद, ऐसे किसी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है। दोनों में से कोई भी पक्ष उक्त प्रदीप के अस्तित्व या गैर-अस्तित्व को स्थापित नहीं कर सका। इसलिए रिपोर्ट अपने आप में संदेह से घिरी हुई है। याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील के इस तर्क पर विवाद करते हुए कि प्रोसेस सर्वर ने आदेश 5 नियम 19 सी. पी. सी. के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया और नियम 17 के तहत वापस किए गए समन को सेवारत अधिकारी के हलफनामे द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, प्रतिवादी-वादी के विद्वान वकील ने प्रोसेस सर्वर द्वारा समन पर समर्थन को हलफनामा के रूप में संदर्भित किया। हालाँकि, उक्त समर्थन शपथ पत्र के सत्यापन के लिए सी. पी. सी. में निर्धारित आवश्यक अवयवों को पूरा नहीं करता है। यहाँ तक कि प्रोसेस सर्वर का नाम भी स्पष्ट नहीं है। शपथ पत्र पर भी ऐसा नहीं है। भले ही उक्त विसंगति को नजरअंदाज कर दिया जाए, लेकिन तथ्य यह है कि कथित स्वतंत्र गवाह प्रदीप की पहचान स्थापित करने में विफलता, प्रोसेस सर्वर द्वारा रिपोर्ट में विशिष्ट कथन के साथ कि कोई स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं था, विरोधाभासी होने के कारण, समन की सेवा पर संदेह की छाया डाल दी है।

(8) प्रत्यर्थी-वादी के लिए विद्वान वकील का तर्क कि एकतरफा कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देने और देरी करने के लिए पारित एकतरफा डिक्री की अनुमति देने की एक सामान्य प्रवृत्ति है, हर मामले में लागू नहीं की जा सकती है या सामान्यीकृत नहीं की जा सकती है।

(9) प्रतिवादी-वादी के विद्वान वकील का अगला तर्क कि याचिकाकर्ता को इनकार करने की आदत थी, इस तथ्य से स्पष्ट था कि वह निष्पादन कार्यवाही में इस तथ्य के बावजूद उपस्थित हुआ कि दीवानी मुकदमे में जारी किए गए नोटिसों और निष्पादन याचिका दोनों की रिपोर्ट 'इनकार'के समान थी, लेकिन वह निष्पादन कार्यवाही में उपस्थित हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह याचिकाकर्ता-प्रतिवादी संख्या 3 का रुख है कि फांसी की याचिका की प्रति उसकी माँ के पास छोड़ दी गई थी, जिसने कथित तौर पर समन को अस्वीकार कर दिया था और उसके बाद, फांसी की याचिका की प्रति देखकर, उसने आदेश 9 नियम 13 सी. पी. सी. के तहत आवेदन दायर करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। किसी भी मामले में,

यह विश्वास करना कठिन है कि कोई भी जानबूझकर और उद्देश्यपूर्ण रूप से एक एकतरफा डिक्री को पारित करने की अनुमति देने का जोखिम उठाएगा और वह भी इनकार की रिपोर्ट के बाद, जिसे हमेशा 'सेवा'माना जाता है, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि ऐसी स्थिति में वह हमेशा आदेश 9 नियम 13 सी. पी. सी. के तहत आवेदन को खारिज करने का जोखिम उठाएगा।

(10) प्रतिवादी-वादी के लिए विद्वान वकील का अगला तर्क कि आदेश 9 नियम 13 सी. पी. सी. के तहत आवेदन निराशाजनक रूप से समय से वर्जित था, इसलिए, कोई मदद नहीं होगी, एक बार जब अदालत यह निष्कर्ष निकालती है कि याचिकाकर्ता को मुकदमे के लंबित होने के बारे में पता नहीं था क्योंकि यह विवादित नहीं है कि देरी जानकारी की तारीख से शुरू होती है। वर्तमान मामले में, जानकारी की तारीख वह तारीख है जब उसकी माँ को निष्पादन याचिका में समन प्राप्त हुआ और उसने निष्पादन याचिका में समन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह तर्क कि आदेश 9 नियम 13 के तहत आवेदन में जानकारी की किसी भी तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है, ताकि अदालत को जानकारी की उस तारीख के बारे में पता चल सके जिससे सीमा को गिना जा सके, यह भी मदद नहीं करता है क्योंकि याचिकाकर्ता ने आदेश 9 नियम 13 सी. पी. सी. के तहत आवेदन दायर किया था।

(11) प्रतिवादी-वादी के लिए विद्वान वकील का अगला तर्क यह है कि याचिकाकर्ता ने देरी की माफी के लिए आवेदन दायर नहीं किया था और आदेश 9 नियम 13 सी. पी. सी. के तहत आवेदन पर देरी की माफी के लिए आवेदन के बिना विचार नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, विद्वान वकील इस बात पर विवाद करने में सक्षम नहीं हैं कि एक बार जब यह स्वीकार कर लिया जाता है कि आवेदन सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 123 के अनुसार जानकारी की तारीख से समय के भीतर है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा ऊपर अभिनिर्धारित किया गया है, तो देरी की माफी के लिए कोई आवेदन दायर करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, उतरवादी के विद्वान वकील द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं, जबकि पी. कृष्णा कुमारी बनाम ए. कण्ढासमी के मामले में, जिसमें देरी की माफी के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था, मद्रास उच्च न्यायालय की विद्वान एकल पीठ ने कहा कि आदेश 9 नियम 13 के तहत आवेदन जानकारी की तारीख से होने की स्थिति में इसे दायर करने की आवश्यकता नहीं थी। उक्त निर्णय का पैरा 17 इस प्रकार है:-

“17. ऐसा प्रतीत होता है कि परिवार न्यायालय दो बाहरी विचारों से प्रभावित था

- (i) कि एकतरफा आदेश 09.11.2004 पर पारित किया गया था और याचिका लगभग चार साल बाद 14.05.2008 का दायर की गई थी और यह कि इसके साथ नहीं था।

(निर्मलजीत कौर, जे.)

विलम्ब को क्षमा करने के लिए कोई याचिका। (ii) इस बीच, प्रतिवादी ने 01.02.2008 का शादी कर ली और 12.07.2009 पर एक बच्चे को जन्म दिया। हमारे सुविचारित विचार में, उपरोक्त दोनों आधार अस्थिर हैं। समर्थन करने वाले हलफनामे में, अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वैवाहिक घर छोड़ने के बाद, वह अपने पति के साथ फिर से जुड़ने की गहरी उम्मीद में थी और केवल 12.05.2008 पर जब आम दोस्त-वेलु ने उसे पूर्व-पक्षीय तलाक की डिक्री के बारे में सूचित किया, जिसके बारे में उसे पता चला और उसके बाद उसने एक-पक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए याचिका दायर की। जब अपीलार्थी को विधिवत नोटिस नहीं दिया गया था, तो उसने अपनी जानकारी की तारीख से 30 दिनों के भीतर आवेदन दायर कर दिया है। चूंकि याचिका जानकारी की तारीख से समय के भीतर दायर की गई थी, इसलिए परिवार न्यायालय का यह कहना सही नहीं था कि याचिका के साथ देरी को माफ करने के लिए आवेदन नहीं था।”

(12) राम औतार बगौरा बनाम राजस्व बोर्ड इलाहाबाद और 4 बगौरा के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भी इसी तरह का विचार रखा गया था।

(13) प्रतिवादी-वादी के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाया गया अगला तर्क यह है कि याचिकाकर्ता को अनुपस्थित रहने की आदत थी और एक एकतरफा आदेश पारित करने की अनुमति देने का उसका इरादा और आचरण केवल देरी के लिए था, यह निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित आदेश से भी स्पष्ट है, जिसके अनुसार उसे एकतरफा रूप से आगे बढ़ाया गया था और उसके बाद दिनांकित आदेश के अनुसार उक्त आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक आवेदन पर निष्पादन न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। उसी का जवाब देते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बताया है कि उक्त तिथि पर, याचिकाकर्ता-निर्णय देनदार को उक्त तिथि पर एकतरफा रूप से आगे बढ़ाया गया था, आदेश 9 नियम 13 के तहत उनका आवेदन भी साथ-साथ चल रहा था और उसी तारीख के लिए तय किया गया था। उन्हें अपनी प्राथमिकता चुननी थी और उनके लिए आदेश 9 नियम 13 के तहत दायर आवेदन में उपस्थित होना महत्वपूर्ण था और चूंकि वह दोनों मामलों के लिए उपस्थित नहीं हो सके, इसलिए उन्हें निष्पादन याचिका में 05.12.2015 पर पूर्व पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसे अंततः अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश (Sr.Divn) द्वारा रद्द कर दिया गया था। इस तथ्य पर ध्यान देते हुए 11.09.2019 पर। इसलिए, प्रतिवादी-वादी इसका लाभ नहीं उठा सकता है या याचिकाकर्ता के खिलाफ अपने आचरण का उल्लेख करने के लिए ऐसा नहीं कर सकता है।

2 2016(एस. पी.) सी. वी. सी. सी. 787

(14) यह प्रतिवादी-वादी के विद्वान वकील का भी रुख है कि उन्होंने रुपये की पूरी राशि का भुगतान किया था। जिस बैंक के साथ संपत्ति को गिरवी रखा गया था, उसके खाते का निपटान करने के लिए 65 लाख रुपये और इसलिए, यह विश्वास करना मुश्किल है कि याचिकाकर्ता-प्रतिवादी संख्या 3 को दीवानी मुकदमे के लंबित होने के बारे में पता नहीं था जब वह उक्त इमारत में ही रह रहा था और प्रतिवादी-वादी ने भी ऋण चुकाने के लिए उससे सम्पर्क किया था। उक्त तर्क दोनों तरीकों को काटता है। यह समझ में नहीं आता है कि प्रतिवादी-वादी को उस बंधक के बारे में कैसे पता चला जो इमारत में नहीं रह रहा है, जबकि याचिकाकर्ता, जो उसी इमारत में है, को इसके बारे में पता नहीं है। इसलिए, इस स्तर पर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भी तर्क दिया गया है कि अन्य उत्तरदाता-विक्रेता और प्रतिवादी-वादी हाथ और दस्ताने में हो सकते हैं। एकतरफा आदेश को बरकरार रखना सुरक्षित नहीं होगा। याचिकाकर्ता को अपना बचाव करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

(15) अंतिम तर्क कि प्रतिवादी-वादी को सफल होने में कई साल लग गए हैं और उसने कब्जा प्राप्त किए बिना बहुत निवेश किया है, हमेशा निचली अदालत को याचिकाकर्ता-प्रतिवादी को लिखित बयान दायर करने और छह महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार अपने साक्ष्य का नेतृत्व करने का अवसर देने के बाद मुकदमे पर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश देकर सुरक्षित किया जा सकता है, भले ही दिन-प्रतिदिन की सुनवाई हो।

(16) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, पुनरीक्षण याचिका को मन्जूर किया जाता है और दिनांक 30.05.2017 और 19.08.2019 के आदेशों को स्थगित किया जाता है पक्षकारों को दिनांक 22.10.2019 को निचली अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया जाता है। ट्रायल कोर्ट दिनांक 22.10.2019 को, दोनों पक्षों के उपस्थित होने पर इस मुकदमे का फैसला तारीख से छह महीने के भीतर जितनी जल्दी हो सकें मैरिट के आधार पर करने के लिये आगे बढ़ेगा।

सुनील चौपड़ा

स्पष्टीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारीक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।